



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241351
CG-DL-E-23122022-241351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5790]
No. 5790]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6033(अ).—यतः, मै. हिलटॉप एसईजेड डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य में इनागलुरु गांव, श्रीकालहस्ती राजस्व मंडल, चित्तूर जिले में फुटवियर मैनुफैक्चरिंग के लिए बहु-उत्पाद क्षेत्र हेतु एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप.धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप.धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त स्थान के 116.307 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	उप मंडल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	इनगलुरु गांव, श्रीकालहस्ती (एम), तिरुपति जिला	181/4	2	2.133
2.		451		4.638
3.		452	8	1.384
4.		453	9	1.194
5.		454		4.852
6.		455	1	3.460
7.		455	2	0.728
8.		456	7	0.506
9.		457	8	1.008
10.		458	2	3.816
11.		459		3.711
12.		460	1	2.736
13.		482	1	2.800
14.		482	4	0.081
15.		483	1	1.170
16.		483	2	0.546
17.		483	3	1.582
18.		483	13	0.308
19.		483	18	0.097
20.		483	21	0.049
21.		483	23	0.138
22.		483	34	0.028
23.		483	40	0.036
24.		484	1	5.075
25.		484	14	0.089
26.		484	16	0.194
27.		485		5.305
28.		486	1	0.563
29.		486	4	0.688
30.		487	1	2.032
31.		488	1	0.668
32.		491		4.051
33.		492	2	2.092
34.		493		4.051
35.		494		4.051
36.		495		4.043

37.		496		4.043
38.		497		3.642
39.		498		3.642
40.		499		4.654
41.		500		4.654
42.		501		5.123
43.		524	3ए	3.331
44.		525		4.047
45.		526	1	1.174
46.		526	6	0.955
47.		527		3.905
48.		528		2.355
49.		529		2.266
50.		530	3बी	2.614
कुल				116.307

और अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. के-43016(11)/7/2022-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SEZ DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2022

S.O. 6033(E).—Whereas, M/s. Hilltop SEZ Development India Private Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Product SEZ for Footwear Manufacturing at Innagaluru Village, Srikalahasthi Revenue Mandal, Chittoor District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on 24th November, 2022;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 116.307 hectares. The survey numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Sub Division	Area (in Hectares)
1.	Inagaluru Village of Srikalahasthi (M), Tirupathi District	181/4	2	2.133
2.		451		4.638
3.		452	8	1.384
4.		453	9	1.194
5.		454		4.852
6.		455	1	3.460
7.		455	2	0.728
8.		456	7	0.506
9.		457	8	1.008
10.		458	2	3.816
11.		459		3.711
12.		460	1	2.736
13.		482	1	2.800
14.		482	4	0.081
15.		483	1	1.170
16.		483	2	0.546
17.		483	3	1.582
18.		483	13	0.308
19.		483	18	0.097
20.		483	21	0.049
21.		483	23	0.138
22.		483	34	0.028
23.		483	40	0.036
24.		484	1	5.075

25.		484	14	0.089
26.		484	16	0.194
27.		485		5.305
28.		486	1	0.563
29.		486	4	0.688
30.		487	1	2.032
31.		488	1	0.668
32.		491		4.051
33.		492	2	2.092
34.		493		4.051
35.		494		4.051
36.		495		4.043
37.		496		4.043
38.		497		3.642
39.		498		3.642
40.		499		4.654
41.		500		4.654
42.		501		5.123
43.		524	3A	3.331
44.		525		4.047
45.		526	1	1.174
46.		526	6	0.955
47.		527		3.905
48.		528		2.355
49.		529		2.266
50.		530	3B	2.614
Total				116.307

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson <i>ex officio</i> ;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>ex officio</i> ;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;

6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member <i>ex officio</i> ;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 23rd December, 2022 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. K-43016(11)/7/2022-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.